भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2367
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

2367. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना और संचालन की प्रगति क्या है;
(ख) निजी क्षेत्र से अनुमानित 72% योगदान आकर्षित करने पर विशेष ध्यान देते हुए पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 50,000 करोड़ रूपये के लक्षित वित्तपोषण को प्राप्त करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) एनआरएफ किस प्रकार राज्य विश्वविद्यालयों सहित सभी प्रकार के विषयों और संस्थानों में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देगा; और
(घ) भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के संबंध में क्या पहल की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाकर तथा भारतीय संस्थानों को उच्च वैश्विक रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके विदेशी छात्रों को कैसे आकर्षित किया जा रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना एएनआरएफ अधिनियम 2023 द्वारा फरवरी, 2024 में की गई है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एएनआरएफ की कार्यकारी परिषद (ईसी) और शासी बोर्ड की स्थापना की गई है।

एएनआरएफ ने लक्षित वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यनीति शुरू की है, जिसमें परोपकारी संगठनों के साथ साझेदारी, उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के मिशन (एमएएचए) के अंतर्गत मिशन-मोड कार्यक्रमों (नकद/वस्तु) में उद्योग का योगदान शामिल है। डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए प्रधानमंत्री फेलोशिप में सार्वजनिक-निजी वित्तपोषण मॉडल, जिसमें फेलोशिप सहायता का **50%** भाग लेने वाले उद्योग द्वारा प्रदान किया जाता है।

एएनआरएफ ने पीएआईआर (त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी) कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे राज्य विश्वविद्यालयों सहित उन संस्थानों, जो उन्हें हब और स्पोक ढांचे में पूरी तरह से स्थापित शीर्ष स्तरीय शोध संस्थानों के साथ जोड़कर एक मेंटरशिप मोड में स्थापित करते हैं, की शोध क्षमता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एएनआरएफ ने कई व्यापक कार्यक्रम/योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे उन्नत अनुसंधान अनुदान (एआरजी), प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान (पीएमईसीआरजी) आदि, जो देश भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायक वातावरण बनाने हेतु शैक्षणिक संस्थानों में युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एएनआरएफ ने पीएचडी पूरी करने के बाद युवा शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल फ़ेलोशिप (एनपीडीएफ) कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो उन्हें देश में बनाए रखने में कारगर है। इसके अलावा, राष्ट्रीय विज्ञान पीठ, जे. सी. बोस अनुदान और प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रख्यात वरिष्ठ वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हैं। इन पहलों का उद्देश्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग के वैज्ञानिकों और संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना भी है।

एनईपी 2020 के विज़न के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एफएचईआई) के शाखा परिसरों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए "यूजीसी (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम 2023" जारी किए हैं। इस विनियम के तहत, आज तक 12 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी द्वारा आशय पत्र (एलओआई) जारी किए जा चुके हैं। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना परिसर शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग संबंधी विनियम भी जारी किए हैं ताकि युग्मित, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम प्रदान किए जा सकें।

इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम आरंभ किया गया है और जिससे अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकर्षित हो सकें। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (एसपीएआरसी) को पुनर्गठित किया गया है ताकि शीर्ष भारतीय संस्थानों और 28 चुनिंदा देशों के अग्रणी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देकर अनुसंधान को सुदृढ़ किया जा सके और भारत की वैश्विक शैक्षणिक उपस्थिति और अनुसंधान क्षमता को बढ़ाया जा सके।

*****